सभी प्रकार की सरकारी सहायताओं से मुक्त, खोजी पत्रकारिता का तेज बढ़ता अखबार

दैनिक

themovementofindia.in

द मूवमेंट ऑफ़ इंडिया

RNI No. RAJHIN/2012/48876
पोस्टल पंजीयन नं. भीलवाड़ा / 2025-2027

खोजी खबरें-तेज नजरें

प्रेरणा स्रोत - स्व. चुन्नीलाल सालवी

ये अखबार ही नहीं क्रांति का अभियान है। मानवता एवं लोकतंत्र का सजग प्रहरी, ये दुष्टों की मौत का सामान है।

वर्ष - 14 अंक -38 | शनिवार, 02 अगस्त 2025 | संपादक - दयाराम दिव्य | सहसंपादक - चाहत सालवी | मूल्य - 2 रू.

राजकीय छात्रावासों की उपेक्षा का आरोप, जर्जर राजकीय छात्रावास भवनों की सूद ली जाये

मुख्यमंत्री एवं समाज कल्याण मंत्री को भेजा ज्ञापन, जिला कलेक्टर से कार्यवाही की मांग ...

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

दयाराम दिव्य

भीलवाड़ा – बाबा रामदेव समता आंदोलन समिति, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा सहित दलित संगठनों ने झालावाड़ स्कूल भवन गिरने के बाद पूरे प्रदेश में राजकीय कार्यालयों एवं प्रदेश के सभी स्कूलों के जर्जर भवन, पेयजल, शौचालय सहित भवनों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट तैयार कर सर्वे किया जा रहा है तथा खराब भवनों को गिराने के भी निर्देश दिये गये है, लेकिन प्रदेशभर में भीलवाड़ा जिले सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों के छात्र-छात्रों के भवन खस्ताहाल एवं जर्जर अवस्था में है, तथा पेयजल एवं अन्य सुविधाऐं खराब है, लेकिन सरकार व जिला प्रशासन द्वारा उनकी सूद नहीं ली जाकर मात्र सरकार एवं निजी स्कूलों का ही निरीक्षण कर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें खस्ताहाल भवनों को गिराने एवं उनकी सूची तैयार की जा रही है लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के छात्र-छात्राओं के प्रत्येक जिले में 2 या 3 दर्जन से अधिक छात्रावास संचालित है जो कि गरीब तबके के परिवार के बच्चे होकर आवासीय छात्रावासों में रहकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते है, वहीं सरकार के कस्तुरबा एवं शारदे आवासीय विद्यालय भी प्रत्येक जिले में संचालित है। लेकिन आज तक सरकार एवं जिला प्रशासन ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों का जो कि खस्ताहाल एवं सुविधाऐं के अभाव में है उनकी सूद नहीं ली है एवं ना ही उनके सर्वे एवं निरीक्षण करने की जरूरत समझी है। इसे लेकर बाबा रामदेव समता आंदोलन समिति के प्रदेश संयोजक एवं भाजपा अनुसूचित जाति के जिला उपाध्यक्ष दयाराम दिव्य ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत एवं जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को ज्ञापन भेजकर ऐसे राजकीय छात्रावासों का सर्वे कर खस्ताहाल छात्रावासों के रख-रखाव एवं आवासीय सुविधाओं में सुधार की मांग की है।

भीलवाड़ा की अश्विनी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड:उज्बेकिस्तान की रेसलर को हराया

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा की बेटी अश्विनी विश्नोई ने अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन जीत ली। अश्विनी अपने फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मुखायो राखीमजोनोवा से 3-0 से जीती।वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली वे प्रदेश की पहली महिला पहलवान बन चुकी हैं।

2 साल में जीते 5 गोल्ड मेडल

अश्विनी ने 2 साल में इंटरनेशनल लेवल पर 5 गोल्ड मेडल जीते हैं । इस बार उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के 65 किलो में भाग लिया, इस चैंपियनशिप में अश्विनी ने पांच मुकाबले में विपक्षी को एक भी अंक नहीं लेने दिया।

फाइनल सहित 5 मुकाबले में विपक्षी को 0 पर समेटा

शिव व्यायाम शाला के कोच कल्याण विश्नोई ने बताया- अश्विनी ने पहले मुकाबले में अल्जीरिया की पहलवान को टेक्निकल आधार पर 10 -0 से हराया। इसके बाद हंगरी की पहलवान को टेक्निकल श्रेष्ठ के आधार पर 13-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की पहलवान को 10-0 से हराया किया।सेमीफाइनल मुकाबले में रूस की पहलवान को 7-0 से हराया और फाइनल मुकाबला उसने उज्बेकिस्तान की पहलवान मुखायो को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता।

भीलवाड़ा पहुंचने पर होगा भव्य स्वागत

अश्विनी के पिता मुकेश बिश्नोई एक फैक्ट्री मजदूर हैं और मां हाउसवाइफ है। अश्विनी 2018 से अपना कुश्ती का सफर शुरू किया। अश्विनी के माता-पिता को पूरा भरोसा था कि वो गोल्ड मेडल जीतेंगी। उसके भीलवाड़ा पहुंचने पर शहर भर के पहलवानों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा।

राजस्थान के तारागढ़ में प्रशासन का एक्शन मोड ऑन, 100 दुकानों पर चला बुलडोज़र

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

शनिवार सुबह करीब 7 बजे, राजस्थान की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर उस वक्त हलचल मच गई, जब सैकड़ों की संख्या में वन विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अमला यहां पहुंचा। आम दिनों में श्रद्धालुओं और दुकानदारों की भीड़ से गुलजार रहने वाला पैदल मार्ग अचानक सुरक्षाबलों और मशीनों से भर गया। तारागढ़ दरगाह जाने वाले पैदल रास्ते पर दोनों ओर बनी कच्ची-पक्की दुकानें एक-एक कर गिरने लगीं। धूल का गुबार, मशीनों की गड़गड़ाहट और अधिकारियों की तेज़ आवाज़ें माहौल को अलग ही रूप दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो रही हो लेकिन ये कार्रवाई किसी देश के दुश्मन पर नहीं, बल्कि सालों से वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ हो रही थी। वन विभाग ने इस कार्रवाई के लिए अजमेर के अलावा टोंक, भीलवाड़ा और नागौर से करीब 250 वनकर्मियों को बुलाया। वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 900 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जिला प्रशासन के अधिकारी, मशीन ऑपरेटर और ठेके पर लाए गए मजदूर पूरी मुस्तैदी से तैनात रहे। कार्रवाई के पहले ही दिन लगभग 100 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। कुल 268 अतिक्रमण चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 60 पर कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। उन्हें फिलहाल नहीं छेड़ा गया।

वन विभाग की ओर से जारी सूची में साफ है कि ये सारी दुकानें वन भूमि पर अवैध रूप से बनी थीं। इन दुकानों को हटाने की प्रक्रिया कई महीने से चल रही थी, लेकिन आज कार्रवाई ने ज़मीन पर असर दिखाया। मौके पर शांति बनी रही, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि प्रशासन पहले से ही कड़ा सुरक्षा घेरा बनाकर आया था।

ग्राउंड पर मौजूद अधिकारी मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। पर प्रशासन ने फोटो और वीडियो खुद साझा किए, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बुलडोज़र चलाए गए और दुकानों को एक-एक कर ढहाया गया।

कलेक्टर लोक बंधु ने कहा, ÷यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है। सभी नियमों का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। छह टीमें बनाई गई हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही हैं। शांति बनी हुई है।

इस पूरे ऑपरेशन को देखकर एक बात साफ है राजस्थान में अब वन भूमि पर कब्जा कर दुकानें खड़ी कर लेने का दौर खत्म होने जा रहा है। सरकार और प्रशासन का यह संदेश बिल्कुल साफ है कानून से ऊपर कोई नहीं। तारागढ़ का ये पैदल मार्ग सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि कारोबारियों के लिए भी कमाई का जरिया रहा है। लेकिन अब वह हिस्सेदारी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, जो वैध रूप से व्यवसाय करते हैं।

कैमरे की एंट्री भले बंद हो, लेकिन बुलडोज़र की हर एक आवाज़ आज तारागढ़ की पहाड़ियों पर गूंज रही थी। और वह आवाज़ सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रही थी, एक सिस्टम का नया आदेश भी सुना रही थी- अब कब्जा नहीं, कानून चलेगा।

फब्तियां कसने से रोका, घर में घुसकर परिवार से मारपीट:भाई बोला- बहन को चाकू मारा

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

बहनों से छेड़छाड़ और फब्तियां कसने से रोका तो बदमाशों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया। आरोपियों ने 2 नाबालिग लड़कियों, उनके पिता और भाई के साथ तलवारों, पाइप और चाकू से हमला कर दिया।

इस हमले में परिवार की 2 नाबालिग लड़कियों सहित कुल 4 घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मामला भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना इलाके का शुक्रवार देर रात का है।

बहनों को देख फब्तियां कसते थे बदमाश

पीड़ित भाई ने पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। भाई ने रिपोर्ट में बताया- दो लड़के हैं, जिनका नाम मोनू पठान और दानिश नीलगर है। ये दोनों मेरी बहनों को आए दिन परेशान करते हैं। उन्हें देखकर फब्तियां कसते और छेड़छाड़ करते हैं। इसको लेकर कुछ दिन पहले हमने उन्हें समझाया भी था।

लाठियां, चाकू लेकर घर में घुसे, मारपीट की

रिपोर्ट में पीड़ित भाई ने बताया- कल (शुक्रवार) रात वह घर पर खाना खाने के लिए आया। तब दोनों अपने कुछ साथियों के साथ तलवार, चाकू, लाठी, पाइप लेकर हमारे घर में घुस गए और आते ही हमारे साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीच बचाव में आई दोनों बहनों को मारा। पिताजी पर भी हमला किया। जब रोकने के लिए पीड़ित ने बीच-बचाव किया तो उसे पीटा। इस दौरान चाकू एक बहन को लग गया। वहीं बदमाशों ने दूसरी बहन के सिर पर पाइप से वार किया। इस हमले में दोनों घायल हो गईं जिनका इलाज किया जा रहा है।

हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

पीड़ित ने बताया कि पिछले 6-7 महीने से ये बदमाश परिवार को परेशान कर रहे थे। जान से मारने की भी धमकी दे रहे थे। सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़ितों के बयान लिए और मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू की है।

C M Y K

सम्पादकीय

ऑपरेशन सिंदूर पर बहस

संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई लंबी बातचीत न केवल स्वस्थ, सार्थक और जीवंत रही बल्कि इसने सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को उनके बेहतर रंग में देश के सामने रखा। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह स्पष्ट घोषणा सामने आई कि 'दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा' जिससे वह अस्पष्टता दूर हो गई, जो इस मुद्दे को लेकर बनी हुई थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति और ऑपरेशन सिंदूर के निहितार्थों को बहुत बारीकी से स्पष्ट किया।

दुनिया को संदेश- पीएम मोदी का जवाब केवल विपक्ष के लिए नहीं था। यह सवाल पूरे देश को परेशान कर रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के व्यापार रोकने की धमकी देकर सीजफायर कराने के दावों में कितनी सच्चाई है। हालांकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले भी ट्रंप के दावों को नकार चुके हैं, लेकिन सरकार के मुखिया की तरफ से आया जवाब पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि भारत ऐसे फैसले किसी के दबाव में नहीं लेता। संयम के साथ शक्ति- पाकिस्तान के साथ टकराव के किसी भी मोड़ पर भारत का इरादा संघर्ष बढ़ाने का नहीं था। सरकार की ओर से खुली छूट होने के बावजूद भारतीय सेना की कार्रवाई सटीक, संतुलित और गैर-उकसावे वाली थी। भारत इस लक्ष्य के साथ उतरा था कि सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आतंक के आकाओं को सबक सिखाना है। यह संयमित रुख दिखाता है कि भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, तो उसे करारा जवाब देने में संकोच नहीं करेगा।

पीएम ने डिफेंस सेक्टर में सुधार से लेकर दुनिया में भारतीय हथियारों की बढ़ती मांग तक पर सिलसिलेवार ढंग से बात रखी। उन्होंने हर उस पहलू को छुआ, जिसे लेकर हाल में बहस बढ़ी है। आमतौर पर राजनीति में मुद्दे नारों के शोर में खो जाते हैं, लेकिन पीएम के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जिस तरह का जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार दिखाया उसकी सराहना की जानी चाहिए।मॉनसून सत्र का काफी वक्त हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। विपक्ष की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो। लंबी चर्चा हुई, विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए अपने सारे संदेह और सवाल सदन में रखे, सरकार ने अपने ढंग से उनके जवाब भी दे दिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सत्र के बचे हुए हिस्से में संसद में हंगामा, शोरगुल और बॉयकॉट नहीं बल्कि स्वस्थ, सार्थक चर्चा और सवाल-जवाब देखने को मिलेंगे।

प्रधान संपादक - दयाराम दिव्य

भामाशाह एडवोकेट रामकुमार प्रजापत ने विद्यालयों में किए 200 बैग वितरित

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा (बिजेंद्र सिंह लोढा) निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय व राजकीय प्राथमिक विधालय जालखेड़ा के दो सौ छात्र छात्राओं को स्कूल बैग वितरण समारोह में प्रधान कृष्णसिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ समारोह में प्रधान राठौड़ ने उपस्थित छात्र छात्राओं को सम्बोधित करते हुए सयंम, अनुशासन के साथ कड़ी मेंहनत कर शिक्षा व खेल क्षेत्र में अपना व अपने परिवार के साथ गांव का नाम रोशन करने की बात कही ।

उन्होंने विधालय के भौतिक शैक्षिक विकास के लिए भामाशाह प्रजापत सहित सभी का आभार जताया । इस अवसर पर भामाशाह अधिवक्ता प्रजापत ने छात्र छात्राओ के शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा तैयार रहने की बात कही । भामाशाह अधिवक्ता रामकुमार प्रजापत ने विधालय के समस्त करीब दौ सो छात्र छात्राओं को स्कूल बैग वितरित किये गए कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ममता महर्षि व प्रधानाध्यापिका प्रेरणा सनाढ्य ने इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत अभिनन्दन किया गया इस अवसर पर कई ग्रामीण उपस्थित थे ।

साधारण मुकाम से एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी

जैसलमेर के पूर्व विधायक रुपा राम जी की बेटी

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

राजस्थान की सुनहरी रेत से उठी एक साधारण बेटी, आज प्रदेश की कानून व्यवस्था का मजबूत स्तंभ बन चुकी है। उनका नाम है प्रेम धनदेव, जो न केवल एक कर्मठ पुलिस अधिकारी हैं, बल्कि मेघवाल समाज की प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनकी यात्रा सिर्फ एक पद की नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मबल और सेवा के संकल्प की कहानी है।

साधारण शुरुआत से असाधारण मुकाम तक

जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिले की पृष्ठभूमि से आने वाली प्रेम धांदेव ने बचपन से ही सपनों को बड़ा देखा और उन्हें हासिल करने की जिद भी रखी। उन्होंने बानस्थली विद्यापीठ और हैदराबाद विश्वविद्यालय से ब्रश्व और स्क्र जैसी उच्च शिक्षा हासिल की। लेकिन उनके भीतर

समाज के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून था—यही उन्हें राजस्थान पुलिस सेवा में ले आया।

एक संवेदनशील और समर्पित पुलिस अधिकारी

आज वे राजस्थान पुलिस में डीवाईएसपी (उप अधीक्षक) के पद पर कार्यरत हैं। लॉकडाउन जैसे कठिन समय में उन्होंने ना सिर्फ कानून व्यवस्था को संभाला, बल्कि जरूरतमंदों तक राशन, दवा और सहारा पहुंचाया। जोधपुर में एक जमीन विवाद में उन्होंने 3 घंटे तक संवाद कर पूरे परिवार को आत्महत्या से रोका—यह केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक मां जैसी ममता और बहन जैसा भरोसा देने वाली नेता का कार्य था।

मेघवाल समाज की प्रेरणा

प्रेम धनदेव केवल एक अफसर नहीं हैं—वे मेघवाल समाज की एक प्रतीकात्मक छवि हैं, जो यह दिखाती हैं कि मेहनत, शिक्षा और हिम्मत के बल पर कोई भी समाज ऊँचाइयों को छू सकता है। जहां कभी समाज को पिछड़ा कहा जाता था, आज वही समाज राज्य सेवा, प्रशासन, शिक्षा और तकनीक में नया इतिहास लिख रहा है।

युवाओं के लिए संदेश

कठिनाईयाँ आएंगी, लेकिन अगर हौसला बुलंद है तो रास्ते भी खुद बनते हैं। समाज को बदलने के लिए खुद को बदलो। पढ़ो, बढ़ो और संघर्ष करो। **- प्रेम धांदेव**

अंत में

प्रेम धनदेव जैसी बेटियां सिर्फ अपने माता-पिता का नहीं, पूरे समाज का सिर गर्व से ऊँचा करती हैं। उनके पदचिन्हों पर चलकर मेघवाल समाज के युवा ना सिर्फ अपनी पहचान बना सकते हैं, बल्कि हजारों की जिंदगी संवार सकते हैं।

बनास नदी के किनारे स्थित थला की माता मंदिर पुल कभी भी बन सकता हे हादसे का कारण

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

हमीरगढ़ (अनिल डांगी) उप खण्ड क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवली में बना थला की मातेश्वरी का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो बनास नदी के किनारे बना हे लोगों के आने जाने के लिए पुल बना हुआ हे जो करीब 100 साल पुराना हो चुका है और न जाने कितने भक्त वह उन के वाहन निकलते हैं रविवार के दिन भक्तों की संख्या 1000 से 1500 तक होती है मातेश्वरी रात को बड़ी संख्या में जागरण होते हैं आजू-बाजू के गांव देवली भैंसाकुण्डल खैराबाद राजोला नाथडीयास पुर आदि गांव के लोग बड़ी संख्या में आते हैं और आस पास के गांवो से लोग माता रानी के दर्शन के लिए आते हे गांव वालों की मांग प्रशासन से अपील स्कूलों के बच्चे पिकनिक मनाने भी आते हैं अगर कोई भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी पुल का निरीक्षण किया जाए और उसकी मरम्मत की जाए

भोपाल में आयोजित होने वाली तेराकी प्रतियोगिता में इंडियन पब्लिक स्कूल के तैराक भाग लेंगे

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

शाहपुरा राजेन्द्र खटीक। शाहपुरा उपखंड मुख्यालय के आईपीएस स्कूल के होनहार बच्चे भोपाल में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे।स्कूल के प्रिंसिपल खुशनूर बानो ओर पीटीआई महेंद्र वैष्णव ने बताया कि भोपाल में 04 अगस्त से 08 अगस्त तक एनआईटी ग्लोबल डिस्कवरी अकैडमी में सीबीएसई जोनल लेवल राज्य स्तरीय स्विमिंग टूर्नामेंट में इंडियन पब्लिक स्कूल शाहपुरा के छात्र रणवीर सिंह मीना,वीर सिंह मीना,ध्रुवजीत सिंह भाटी,विश्व प्रताप सिंह भाग लेंगे।

छतरियां बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है शिव धाम

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

आकोला(रमेश चंद्र डाड)कस्बे में बनास नदी किनारे स्थित छतरियां बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है शिव धाम। स्थानीय निवासी विनोद असावा ने बताया कि भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर आकोला गांव में (शाहपुरा बेगू) मार्ग पर बनास नदी किनारे स्थित शिव मंदिर को पुराने नाम से छतरियां बावड़ी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि यह शिवलिंग एक बडी शिला पर बना हुआ है। जो प्राचीन काल से बनास नदी के किनारे स्थापित था ।आज

के 100 वर्ष पूर्व समाजसेवी शिव नारायण अग्रवाल ने इस शिवलिंग पर एक छतरी बनाई और पास में ही एक पानी की बावड़ी थी तब से इसका नाम छतरियां बावड़ी पड़ गया। बदलते समय में यहां पर संत महात्माओं ने अपना डेरा जमाया जिसमें रामकिशोर दास जी महाराज ,केशव जी महाराज, जागेश्वर दास जी महाराज, रामलला दास जी महाराज, उपमन्यू दास जी महाराज तथा वर्तमान में महंत रामस्नेही दास जी महाराज के सानिध्य में इस मंदिर की सेवा पूजा अर्चना का कार्य चल रहा है। और एक भव्य शिखर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे पूर्व शिवलिंग को मंदिर प्रांगण में स्थापित किया गया है। मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने पर फिर से निज मंदिर में स्थापित किया जाएगा। आने वाले समय में इस स्थान की भव्यता को चार चांद लगायेगा। महंत ने बताया कि हर वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर,वैशाख माह ,सावन माह व नवरात्रि महोत्सव, दीपावली पर्व,, गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालुओ की भीड़ उमड़ती है।

पहुंच से बाहर सोना!

रेट के गहनों की शायद ही पहले कभी मांग रही हो, जैसी
हरेट सोने का भाव भी प्रति दस ग्राम लगभग 35 हजार
सोने का तकरीबन 59 हजार रुपये है। भारत में स्वर्ण
ं की उम्मीद अब हलके जेवरात पर टिकी है। कारण
ा हो जाना है, जिससे भारत के महंगे गहने अब आम
हुंच से बाहर हो गए हैं। नौ कैरेट और 14 कैरेट के गहनों
। कभी ऐसी मांग रही हो, जैसी अब बनी है। जबकि इस
ोने का भाव भी प्रति दस ग्राम लगभग 35 हजार रुपये और
का तकरीबन 59 हजार रुपये है। प्रति दस ग्राम 24 कैरेट
ा एक लाख रुपये के पास है, जबकि 22 कैरेट 91-92 हजार
ल पा रहा है। भारत में सोने के गहनों का खास सांस्कृतिक महत्त्व
. मगर अब उन लोगों के लिए ऐसे तकाजों को पूरा करना मुश्किल हो
. है, जिनका बजट एक लाख रुपये कम हो। कम बजट वाले खरीदारों
ं बाजार से बाहर हो जाने का ही नतीजा है कि बीते जून में सोने की बिक्री में 60 फीसदी की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज हुई। ऐसी गिरावट सिर्फ कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय देखने को मिली थी। लेकिन वह असाधारण समय था। बहरहाल, सोने की ये महंगाई वक्ती नहीं है। यह विश्व वित्तीय व्यवस्था में तेजी से आ रहे बदलावों का नतीजा है। 1971 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, जब दीर्घकालिक ट्रेंड के तौर पर सेंट्रल बैंक एवं निवेशक डॉलर की जगह सोने का भंडार बना रहे हैं। कई देश तो डॉलर बेच कर सोना खरीद रहे हैं। यह अमेरिकी डॉलर की गिरती साख और उसमें घट रहे भरोसे का संकेत है। अब तक डॉलर विश्व मुद्रा है, मगर अनेक देश अब अपनी मुद्राओं में अंतरराष्ट्रीय भुगतान को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में अपनी मुद्रा को मजबूत बनाने के क्रम में उनके लिए अपने भंडार में सोना रखना जरूरी हो गया है। तो गुजरे तीन वर्षों में जितने संगठित ढंग से सोने की खरीदारी हुई है, वैसे गुजरे दशकों में कभी नहीं हुआ। नतीजतन दुनिया भर में सोना महंगा हुआ है। और इसी की मार भारतीय उपभोक्ता झेल रहे हैं।

सवाल जहां के तहां!

दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में लंबी चर्चा और उस पर सरकार के जवाब के बाद भी गंभीर एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्न अब अनुत्तरित बने रह जाते हैं। बहसें दोनों पक्षों के बीच आरोप- प्रत्यारोप का मौका भर बन कर रह जाती हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दो दिन की गरमागर्म बहस के बावजूद वे सवाल जहां के तहां हैं, जो मई में चार दिन तक चली इस लड़ाई के दौरान उठे थे। देश को आज भी यह आधिकारिक रूप से मालूम नहीं है कि क्या 6-7 मई की रात भारत के लड़ाकू विमान गिरे, ऑपरेशन सिंदूर अपना मकसद को साधने में कितना कामयाब हुआ और 10 मई को अचानक इसे रोक देने पर भारत सरकार क्यों राजी हो गई थी? सरकार की तरफ से दावा जरूर किया गया कि भारत ने अपना मकसद पूरा किया और युद्धविराम कराने में "किसी विश्व नेता" की भूमिका नहीं थी। मगर ये दावे पहले भी किए गए हैं। आखिर यह कहने का मतलब क्या है कि भारत का मकसद पूरा हो गया? क्या पाकिस्तान में आतंकवाद का ढांचा नष्ट हो गया है और भारत अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की चिंता से मुक्त हो जाने की स्थिति में है? फिर सवाल "किसी विश्व नेता" की नहीं, बल्कि सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के ढाई दर्जन बार किए दावों को लेकर है कि युद्धविराम उन्होंने करवाया। ऐसे में जब तक सरकार सीधे उनका नाम लेकर दावों का खंडन नहीं करती, इससे जुड़े प्रश्न बने रहेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में चर्चा और उस पर सरकार के जवाब के बाद भी अब गंभीर एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित बने रह जाते हैं। बहसें महज आरोप- प्रत्यारोप का मौका बन जाती हैं, जिस दौरान दोनों पक्षों में यह दिखाने की होड़ रहती है कि उनमें किसने अपने शासनकाल में क्या हासिल किया? दूसरे पक्ष को छोटा दिखाना इसी प्रवृत्ति का दूसरा पहलू है। गौरतलब है कि बहस ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही थी। इस पर नहीं कि जवाहर लाल नेहरू की क्या नाकामियां थीं या इंदिरा गांधी कितनी साहसी नेता थीं! कुछेक भाषणों को छोड़ दें, तो ज्यादातर वक्त संसद ऐसे ही अप्रासंगिक दावों एवं आरोपों में उलझी रही। परिणाम यह है कि लंबी बहस के बावजूद दोनों पक्ष अपनी- अपनी राय पर कायम हैं। मतलब यह कि ध्रुवीकृत समूहों के बीच सार्थक संवाद की भूमिका संसद फिर नहीं निभा पाई।

बहस तो अधूरी ही रह गई!

संसद के मानसून सत्र का इंतजार सबको था। इंतजार इसलिए था क्योंकि सरकार ने पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की अपील पर ध्यान नहीं दिया था। संसद में खड़े होकर विपक्ष को जवाब देने और देश के नागरिकों को इसकी सचाई बताने की बजाय सरकार दुनिया भर के देशों में डेलिगेशन भेज कर उनके सामने अपना पक्ष रख रही थी। तभी जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई और यह तय हुआ कि दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार, 28 जुलाई को पहलगाम कांड व ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी तो उम्मीद थी कि इनसे जुड़े समूचे घटनाक्रम की सचाई सामने आएगी। सरकार हर पहलू के बारे में जानकारी देगी। विपक्ष जो सवाल पहले से उठा रहा है और जो सदन में सवाल उठाए जाएंगे, उनका वस्तुनिष्ठ तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि दो दिन की लंबी चर्चा और प्रधानमंत्री के लंबे भाषण के बाद भी बहस अधूरी ही रह गई। इस बहस के बाद यह धारणा भी मजबूत हुई कि भारत में संसदीय बहसों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और सारी संसदीय बहस सिर्फ राजनीति साधने और चुनावी लाभ के लिए होती हैं। किसी भी सभ्य लोकतंत्र में संसदीय बहसें ऐसी नहीं होती हैं। भारत में भी कोई संविधान सभा की बहस के दस्तावेज पढ़े तो उसे भी आज जो हो रहा है उस पर शर्म ही आएगी। बहरहाल, पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कौन से सवाल थे, जिनके वस्तुनिष्ठ जवाब की जरूरत थी, उस पर आने से पहले एक रूपक के जरिए इस बहस को समझते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति उनसे बिजली नहीं आने की शिकायत कर रहा था। वह व्यक्ति कह रहा था कि सिर्फ तीन घंटे बिजली आती है और अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर तक यह बात सुनने के बाद माननीय बिजली मंत्री ने अपने गले में पड़ी ढेर सारी मालाएं निकालीं और जोर से नारा लगाया, जय श्रीराम! बात वहीं खत्म हो गई। लोकसभा में पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर पर सत्तापक्ष यानी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सभी नेताओं का भाषण इसी श्रेणी का था। सवालों का जवाब देने की बजाय सत्तापक्ष के लगभग सारे वक्ता सेना के शौर्य का गुणगान कर रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अपनी छाती ठोक रहे थे और 77 साल पहले वाली सरकार की कमियां गिना रहे थे। सोचें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब एक सौ मिनट के भाषण में 14 बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया! क्या पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा में देश के लोग यही सुनना चाहते थे? नेहरू की गलतियां थीं या इंदिरा गांधी ने गलती की या उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने गलतियां कीं तभी तो देश की जनता ने भाजपा और नरेंद्र मोदी को मौका दिया है! अब तो देश के लोग इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। नेहरू का या इंदिरा गांधी का नाम लेकर किसी भी तात्कालिक मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता है। नेहरू की गलतियां अपनी जगह हैं, जिनके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी एक सौ साल से बोल रहे हैं। लेकिन लोग तो यह जानना चाहते थे कि पर्यटकों की उतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद पहलगाम घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं तैनात था? लोग यह जानना चाहते थे कि आतंकवादी 20 मिनट तक तांडव करते रहे और उतनी देर में एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचा और आतंकवादियों के जवाब देने के लिए एक भी गोली नहीं चली तो ऐसा क्यों हुआ? यह तो संभव नहीं है कि नेहरू या इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से रोक दिया था? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए था और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री के इतने लंबे भाषण में एक बार भी पहलगाम में

मारे गए 26 बेकसूर नागरिकों का जिक्र नहीं आया। देश के लोग जानना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया तो फिर 88 घंटे के भीतर सीजफायर क्यों हो गया? जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से गुहार लगाई कि पाकिस्तान अब और हमला नहीं झेल सकता है तो युद्धविराम हो गया। सवाल है कि पाकिस्तान मजबूर था कि वह हमारा हमला नहीं झेल पा रहा था लेकिन हमारी क्या मजबूरी थी? हमने क्यों सीजफायर स्वीकार कर लिया? अगर स्वीकार किया तो पाकिस्तान के सामने क्या शर्तें रखीं और क्या उसने हमारी कोई शर्त स्वीकार की? दुनिया के तमाम सामरिक और रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि भारत को दो तीन दिन और हमले जारी रखने चाहिए थे ताकि पाकिस्तान का सैन्य ढांचा स्थायी रूप से खत्म हो और उसके सैन्य नेतृत्व की कमजोरी पाकिस्तान की जनता के सामने जाहिर हो। लेकिन इसका उलटा हुआ। बिना शर्त युद्धविराम की वजह से पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को छाती ठोक कर जीत का दावा करने का मौका मिला और आज पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व पहले से ज्यादा मजबूती और ताकत के साथ भारत विरोधी गतिविधियों में लगा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी उसकी प्रतिष्ठा कम होने की बजाय बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ कि भारत जीतता हुआ पक्ष था लेकिन उसने बिना शर्त सीजफायर कर लिया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। सीजफायर कराने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने सीजफायर नहीं कराई। वे संसद में वही बोले, जो ब्राजील में जी 7 देशों के सम्मेलन में बोले थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई थी। उन्होंने यह भी दोहराया कि अमेरिका के उप राष्ट्रपति जीडी वेंस ने उनसे कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है तो उन्होंने कहा कि हम उससे बड़ा हमला करेंगे। सवाल है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया और हमें हमला करने की जरुरत नहीं पड़ी? कुछ तो हुआ परदे के पीछे, जिसके बाद सीजफायर हुआ! प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बताना चाहिए था कि क्या हुआ, जिसकी वजह से बिना शर्त सीजफायर की नौबत आई। विडम्बना यह है कि जिस समय प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रूकवाई लगभग उसी समय अमेरिका में ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग रूकवाई। ध्यान रहे दुनिया का कोई नेता सीजफायर का श्रेय नहीं ले रहा है, सिर्फ ट्रंप ले रहे हैं। इसलिए दुनिया कि किसी नेता ने नहीं रूकवाई कहने की बजाय अगर प्रधानमंत्री मोदी एक बार कह दें कि ट्रंप ने जंग नहीं रूकवाई तो बात खत्म हो। लोग यह सुनना चाहते थे लेकिन यह नहीं कहा गया। एक और अहम बात जो पूरी चर्चा में मिसिंग रही वह ये है कि भारत को कितना नुकसान हुआ। पेंसिल टूटने की बात कही गई लेकिन यह भारत के प्रतिरक्षा प्रमुख यानी सीडीसी जनरल अनिल चौहान की बात का स्पष्टीकरण नहीं है और न जकार्ता दूतावास के भारत के डिफेंसे अताशे कैप्टेन शिवकुमार की बात का जवाब है। दोनों ने भारत के नुकसान की बात कही थी। कैप्टेन शिवकुमार ने तो नुकसान के लिए राजनीतिक फैसले को जिम्मेदार बताया था। लेकिन पूरी बहस में सरकार की ओर से इसका जवाब नहीं दिया गया। भारत को कितना और क्या नुकसान हुआ यह बताया जाना चाहिए था या फिर यह कहा जाना चाहिए था कि सेना के दोनों अधिकारियों ने जो कहा वह सही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीमित जंग में चीन सक्रिय भागीदार था और यह बात भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। उसने पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ अपने हथियारों का परीक्षण किया। भारत के खिलाफ युद्ध में चीन की सक्रिय भागीदारी के बावजूद रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों चीन के दौरे पर गए और जब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हुई तो उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। यह सही है कि इतने बड़ा घटनाक्रम के बावजूद भाजपा और नरेंद्र मोदी को कोई राजनीतिक नुकसान होता नहीं दिख रहा है। लेकिन समर्थक वर्ग को परवाह नहीं है क्या इस वजह से इतने अहम सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा?

दिल्ली की गाड़ियां, अब सुध आई!

दिल्ली की सरकार को दिल्ली वालों की गाड़ियों की अब जाकर फिक्र हुई है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां उसने यह तर्क दिया है कि पुरानी गाड़ियों को सड़क पर से हटाने के लिए उनकी उम्र नहीं, बल्कि फिटनेस देखनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि सिर्फ 15 साल पुरानी हो जाने की वजह से गाड़ी को नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उसके प्रदूषण का स्तर चेक करके तब उसे हटाना चाहिए। यह बहुत समझदारी और तार्किक बात है लेकिन सरकार को और प्रदूषण पर सुझाव देने वाली एजेंसी को पहले क्यों नहीं सूझी? यह भी सवाल है कि एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को यह सुझाव दिया तो वहां दिल्ली की सरकार ने इसका विरोध क्यों नहीं किया था? ऐसा लग रहा है कि मध्य वर्ग की नाराजगी को लेकर सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग

शुरू हुई है उससे घबरा कर सरकार पुराने फैसले से पीछे हट रही है। ध्यान रहे पिछले कई सालों से यह अभियान चल रहा था। भले इस साल एक जुलाई से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने का अभियान शुरू हुआ था लेकिन 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को सड़क से हटाने के अभियान कई साल पहले शुरू हो गया था। लोगों की दरवाजे के सामने खड़ी गाड़ियां उठाई गईं। दिल्ली नगर निगम के लोग टीम लेकर दिल्ली की कॉलोनियों में घूमते थे और फोन ऐप पर गाड़ियों के नंबर चेक करके देखते थे कि कौन सी गाड़ी कितनी पुरानी है। अगर समय सीमा से ज्यादा पुरानी गाड़ी दिख जाती थी तो वहीं नोटिस देते थे, जुर्माने का भय दिखाते थे और गाड़ी उठा कर ले जाने की धमकी देते थे। मजबूरी में लोग स्क्रैप वालों से या एजेंसी वालों से गाड़ियां बेचते थे। एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, जो अब भी कर रहा है। उसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार, न्यायपालिका और मीडिया सबकी है।

दुबई अब ट्रांज़िट शहर नहीं घर भी है!

दुबई अब महज़ घूमने की एक जगह नहीं है। वह भारत के लोगों का ठिकाना हो गया है। अगर कैलेंडर पर लंबा वीकेंड दिखे, तो तय मानिए कोई न कोई जान-पहचान वाला दुबई के लिए बैग पैक कर चुका होगा। बीते कुछ सालों में यह शहर चुपचाप गोवा और मनाली को पीछे छोड़, शहरी भारतीयों के लिए डिफॉल्ट छुट्टी डेस्टिनेशन बन गया है। अब पहाड़ी कैफ़े की जगह इंस्टाग्राम पर अटलांटिस के पूलसाइड ब्रंच की तस्वीरें छाई रहती हैं। और जब एयर इंडिया दुबई के रिटर्न टिकट उस दाम में देने लगे, जितना श्रीनगर का वन-वे टिकट पड़ता है, तो समझ जाए कि कि रेगिस्तान की उड़ान अब घाटी से भी सस्ती है। फिर भी, मैं कभी दुबई नहीं गई। ना छुट्टी में, ना काम से, ना ट्रांज़िट में। और आज की ग्लोबल हसल कल्चर में, ये अपने-आप में एक सोशल ऐनोमली लगता है। सच कहूँ तो, मैं दुबई की दीवानगी को समझ नहीं पाई। वो आकर्षण, वो जल्दबाज़ी, वो चमक के पीछे भागना—मुझे कभी समझ नहीं आया। बाक़ी बहुत से भारतीयों के विपरीत, मुझे दुबई उतना मनभावक, लाभदायक नहीं लगा, जितना अपना दार्जिलिंग या दीवा। लेकिन आज मैं यदि दुबई शहर के बारे में लिख रही हूँ तो जाहिर है कुछ बदला है। एक हेडलाइन ने मेरा ध्यान खींचाः "2025 की पहली छमाही में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 4.6 करोड़ यात्रियों का स्वागत किया, जबकि क्षेत्रीय एयरस्पेस में बाधा भी थी। इसमें से अकेले भारत के 59 लाख यात्री थे।" मतलब बात सिर्फ़ टैक्स-फ्री शॉपिंग या ऊँची इमारतों की नहीं है। यह शहर अब एक मानसिकता बन गया है—एक माइंडसेट। एक ऐसा नज़रिया, जो दिखावे से आगे जाकर कुछ और भी पेश करता है। मुझे अपने मामा की बात याद आईः "अगर मैंने दो महीने से न्यूज़ नहीं देखी, तब भी मैं बता सकता हूँ किस देश में संकट है—सिर्फ़ यह देखकर कि मेरी बिल्डिंग में कौन नया शिफ्ट हुआ है।" हाल के दिनों में उन्होंने ज़्यादा इज़रायली और फिलिस्तीनी देखे। उससे पहले, रूसी और यूक्रेनी। दुबई अब एक न्यूट्रल ज़ोन बन चुका है—एक भू-राजनीतिक वेटिंग रूम, जहाँ दुनिया के विस्थापित, मोहभंग से भरे और महत्वाकांक्षी लोग आकर रुकते हैं, खुद को फिर से शुरू करते हैं, और फिर थोड़ा और रुक जाते हैं। और इसी सांस्कृतिक मिश्रण में भारतीय सिर्फ़ टूरिस्ट बनकर नहीं आ रहे—वे यहाँ बस भी रहे हैं। कभी ये शहर रेगिस्तान के किनारे एक छोटा-सा बंदरगाह था। लेकिन अगर दुबई को समझना है, तो उसकी स्टील और चमक को हटाकर इतिहास में झाँकना

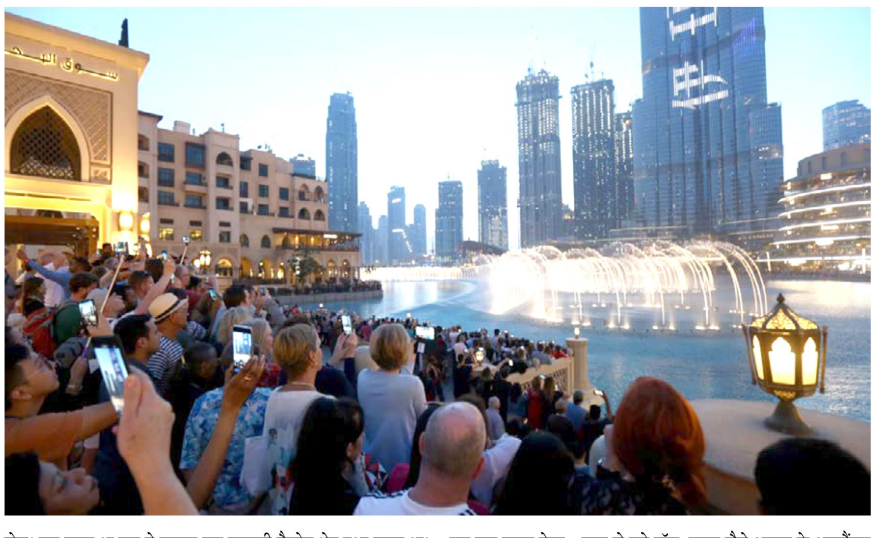

होगा। एक समय था जब ये इलाका एक दलदली मैन्ग्रोव क्षेत्र हुआ करता था। फिर आया 1833, जब बनी यास जनजाति के मक्तूम बिन बुत्ती ने यहाँ डेरा डाला और दुबई क्रीक को अपना ठिकाना बना, इसे स्वतंत्र घोषित किया। अल मक्तूम वंश ने व्यापारिक करों को हटाकर भारत और पाकिस्तान से व्यापारियों का स्वागत किया। लेकिन जब जापानी नकली मोतियों ने बाज़ार बिगाड़ा, तब 1966 में तेल की खोज ने दुबई की कहानी को एक नया, काले सोने वाला अध्याय दे दिया। लेकिन असली क्रांतिकारी मोड़ तेल से नहीं, बल्कि उस पल आया जब तेल की चमक कम होने लगी। तब दुबई टूटा नहीं, उसने खुद को फिर से गढ़ा। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक नया सपना देखा—शहर से बड़े मॉल, खजूर जैसे आकार के आइलैंड्स, और आसमान छूती इमारतें। भविष्य अब तेल से नहीं, पर्यटन से चलेगा। सो अब दुबई की जीडीपी (GDP) का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा टूरिज़्म से आता है—तेल से लगभग दोगुना। सवाल है अब भी वही, पुरानी दुबई भारतीयों के लिए इतनी आकर्षक क्यों है? इतना ही नहीं अब पश्चिमी दुनिया के लिए भी है? कुछ के लिए यह शहर ग्लैमर है, कुछ के लिए सहूलियत। लेकिन बहुत से भारतीयों के लिए ये है—आकांक्षा बिना बेगानगी के। ये शहर ग्लोबल है, फिर भी अपना-सा लगता है। चिकना है, लेकिन सुलभ भी। शेंगेन वीज़ा जैसी कोई ज़रूरत नहीं। मेट्रो में कोई घूरता नहीं। चाहे आप टेक कंसल्टेंट हों, फ़ैशन इन्फ्लुएंसर या इंदौर से आई एक पाँच लोगों की फ़ैमिली—यहाँ आपके लिए एक जगह है। दुबई आपसे घुलने-मिलने की उम्मीद नहीं करता, वो बस आपको आने देता है। यहाँ सब कुछ साफ़-सुथरा है, व्यवस्थित है, और अजीब तरह से असरदार। यह ग्लोबल है, लेकिन ठंडा नहीं। यह लक्ज़री है, लेकिन नखरे वाला नहीं। और यह फिनिशिंग टच के बावजूद, कहीं न कहीं भारतीय-सा लगता है। आज ग्लोबल साउथ से ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स खाड़ी की तरफ़ रुख़ कर रहे हैं। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका से पढ़े-लिखे लोग दुबई को अब मजबूरी में नहीं, पहले विकल्प के तौर पर चुन रहे हैं। वजहें साफ़ हैं—वीज़ा आसान, महत्वाकांक्षा का स्वागत, और सफलता के लिए किसी सांस्कृतिक क्षमा की ज़रूरत नहीं। खाड़ी की सरकारें भी अब बदली हैं—लॉन्ग टर्म वीज़ा, लचीली रेसिडेंसी, और लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत ख़त्म। खाड़ी अब सिर्फ़ मज़दूरों या यूरोपीय प्रवासियों का अड्डा नहीं, बल्कि इंजीनियर, कलाकार, शिक्षक, वकील, शेफ और एंटरप्रेन्योर के लिए भी खुला है। शायद अभी तय नहीं। लेकिन इतना तय है कि दुबई अब महज़ एक लेओवर नहीं रहा—यह वह शहर है जहाँ कुछ नया, चमकदार और टिकाऊ बन सकता है। और मैं? मुझे अब भी नहीं पता कि दुबई मेरे भीतर के पत्रकार, उस लेखक जिसे मैं बनना चाहती हूँ, या मेरे पति जो पहले ही फ़ोटोग्राफ़र हैं—उनके लिए क्या रखता है। यह शहर अब हमें आकर्षित करने लगा है, हाँ। लेकिन क्या यह भीतर तक झकझोरता है? इस शहर की चमक के पीछे क्या ऐसे क़िस्सों की जगह है जो 'क्यूरेटेड' नहीं हैं? क्या यहां वैसी तस्वीरों की गुंजाइश है जो बिना फ़िल्टर के हों, बिना तमाशे के? मैं एक करीबी को जानती हूँ जो इस दुबई को अपना घर बनाने का सोच रहा है। और मैं समझ सकती हूँ क्यों? जब एक शहर जो कभी मछलियों और मोतियों का व्यापार करता था, आज सपनों और डिजिटल भविष्य का एक्सपोर्टर बन गया है—तो ये सिर्फ़ ट्रेंड नहीं हो सकता। शायद यह एक बदलाव है। तो क्या मैं जाऊँगी? शायद। लेकिन सिर्फ़ बुर्ज खलीफ़ा की सेल्फ़ी के लिए नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि यह शहर क्यों चर्चा में है—और क्यों, इस बंद होती दुनिया में, दुबई वो जगह बन गया है जो बाहें फैलाकर स्वागत करता है। क्यों लोग एक बार आते हैं, और फिर चुपचाप यहीं बस जाने का फ़ैसला कर लेते हैं।

-श्रुति व्यास

विराट कोहली के रिटायर होते ही शुभमन गिल निकले आगे... इस लिस्ट में रोहित शर्मा अभी भी आगे

एजेंसी लंदन

भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में चल रहे पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। गिल ने पांचवें टेस्ट की पहले पारी में सिर्फ 21 रन बनाए। एक गलती के कारण वह रन लेने के लिए आगे बढ़े और गस एटकिंसन ने उन्हें रन आउट कर दिया। हालांकि इन 21 रनों की मदद से गिल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। शुभमन गिल अब WTC में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे आगे ऋषभ पंत और रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ओवल टेस्ट के पहले दिन शुभमन गिल 21 रन बनाकर आउट हो गए। WTC में उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। गिल के अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2636 रन हो चुके हैं। WTC में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी:

2731 - ऋषभ पंत (67 पारियां)
2716 - रोहित शर्मा (69 पारियां)
2636 - शुभमन गिल (68 पारियां)
2617 - विराट कोहली (79 पारियां)
2348 - रविंद्र जडेजा (67 पारियां)

ओवल टेस्ट पर हरी पिच पर गेंद इधर-उधर हिल रही थी। गिल ने खुद को संभाला और अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने एक गलती कर दी और अपना विकेट गंवा दिया। वाशिंगटन सुंदर और करुण नायर ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की और दिन का खेल खत्म किया। हालांकि दूसरा दिन शुरू होते ही टीम इंडिया के बाकी 4 विकेट सिर्फ 20 रन पर गिर गए और भारतीय टीम की पारी सिर्फ 224 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए उनके तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने 5 विकेट हासिल किए। एटकिंसन इस सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे थे, लेकिन वे टीम इंडिया पर भारी पड़ गए।

बेन डकेट को जाकर कुछ कह रहे थे आकाश दीप, अगली बॉल पर अंग्रेज ने यूं 'जलील' कर दिया

एजेंसी लंदन

भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टेस्ट मैच 31 जुलाई से ओवल में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन बेन डकेट और आकाश दीप के बीच एक घटना हुई, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। डकेट को गेंद डालने के बाद आकाश दीप कुछ कह रहे थे, जिसका बदला इंग्लिश बल्लेबाज ने अगली बॉल पर लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, आइये जानते हैं। आकाश दीप ने बेन डकेट को मैच के दूसरे दिन एक गेंद डाली, जिसके बाद वह उनके पास गए और कुछ कहने लगे। हालांकि, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस बात की तो जानकारी नहीं है। लेकिन, अगली बॉल पर बेन डकेट ने बदला खूब लिया। उन्होंने आकाश दीप की गेंद पर विकेट के पीछे रिवर्स स्वीप खेलते हुए गजब का छक्का लगाया। इस तरह तेज गेंदबाज को छक्का लगाना किसी बेइज्जती से कम नहीं माना जाता है। 13वां ओवर भारत की तरफ से आकाश दीप डाल रहे थे। उनके ओवर की पांचवीं गेंद पर बेन डकेट स्ट्राइक पर थे। बेन डकेट रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। लेकिन, वह गेंद को टाइम नहीं कर पाए और गेंद उनके बल्ले का एज लेते हुए विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में चली गई। ऐसे में डकेट 43 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। इंग्लैंड के स्टेंड इन कप्तान ओली पोप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ऐसे में भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए। करुण नायर ने टीम इंडिया के लिए सर्वाधिक 57 रन बनाए जबकि इंग्लैंड के लिए गस एटकिंसन ने पंजा खोला।

सुनील गावस्कर ने किया इंग्लैंड को एक्सपोज, पिच को लेकर ऐसा बयान, बेन स्टोक्स गुस्से से लाल होंगे

एजेंसी लंदन

भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश से बाधित रहा। भारत ने 64 ओवर में 6 विकेट खोकर 204 रन बनाए। अगले दिन टीम इंडिया आते ही 20 रन और बनाकर 224 रन पर ऑलआउट हो गई। पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने पिच को लेकर इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण पर सवाल उठाए। उनका मानना है कि इंग्लैंड के पास अच्छे गेंदबाज नहीं हैं इसलिए उन्होंने ऐसी पिच बनाई है। पिच तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित हुई। सुनील गावस्कर ने पिच को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण पर निशाना साधा। इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्स जैसे प्रमुख गेंदबाज नहीं खेल रहे हैं। स्टोक्स इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। आर्चर और कार्स ने भी नियमित रूप से विकेट लिए हैं। गावस्कर ने कहा, 'उनके पास कोई अच्छी गेंदबाजी नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी पिच बनाई है।' उन्होंने आगे कहा, 'स्टोक्स ने विकेट लिए, आर्चर ने विकेट लिए, कार्स ने विकेट लिए। अगर वे नहीं खेल रहे हैं, तो कौन विकेट लेगा? इसलिए उन्होंने ऐसी पिच बनाई है ताकि टंग और अन्य गेंदबाजों को मदद मिल सके।' ओवल की पिच पर घास थी, जिससे गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी। खासकर बादल छाए रहने पर गेंद ज्यादा स्विंग हो रही थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने अपने पहले ही मैच में दो महत्वपूर्ण विकेट लिए। वहीं उन्होंने भारत की पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए। लेकिन जोश टंग और जेमी ओवरटन अपनी लाइन और लेंथ से भटके हुए दिखे। क्रिस वोक्स, जो पांचों टेस्ट मैच खेल रहे हैं फील्डिंग करते समय कंधे में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर चले गए। उनका आगे खेलना संदिग्ध है। गावस्कर का मानना है कि इंग्लैंड ने कमजोर गेंदबाजी आक्रमण के कारण ऐसी पिच बनाई है। वे चाहते थे कि उनके गेंदबाज पिच से मदद लेकर विकेट निकाल सकें। हालांकि, भारतीय बल्लेबाजों ने भी मुश्किल परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया। करुण नायर की अर्धशतकीय पारी टीम के लिए महत्वपूर्ण रही। बारिश के कारण खेल बार-बार बाधित होने से बल्लेबाजों को परेशानी हुई। लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और रन बनाते रहे।

बढ़ती जा रही है अंग्रेजों की हिम्मत... अब जो रूट ने लिया प्रसिद्ध कृष्णा से पंगा, अंपायर्स बीच में कूदे

एजेंसी लंदन

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज अब अपने आखिरी मुकाबले तक आ पहुंची है। इस सीरीज में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जमकर विवाद हुआ। ऐसा ही कुछ 5वें टेस्ट में भी देखने को मिला। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट और भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के बीच तीखी बहस हुई। इंग्लैंड की पारी के 22वें ओवर में रूट और प्रसिद्ध के बीच कुछ कहासुनी हो गई। यह साफ नहीं है कि प्रसिद्ध ने इंग्लैंड के बल्लेबाज से क्या कहा, लेकिन बहस इतनी बढ़ गई कि अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा। रूट वैसे तो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वो आपा खो बैठे। इस छोटी सी झड़प ने पहले से ही रोमांचक चल रहे क्रिकेट के दिन में एक और रंग भर दिया। जो रूट काफी भड़के हुए नजर आ रहे थे। इस बीच उन्होंने क्रीज पर वापस लौटने से पहले प्रसिद्ध कृष्णा को कुछ कहा भी। तभी अंपायर्स बीच बचाव करने लगे। इसी बीच टीम इंडिया के सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल भी अंपायर्स से कुछ बातचीत करते हुए नजर आए। हालांकि ये मामला बहुत लंबा नहीं चला और खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर वापस लौट गए। पहले सेशन में इंग्लैंड ने भारत को सिर्फ 224 रनों पर आउट कर दिया और लंच तक 109/1 रन बना लिए थे। जैक क्रॉउली ने 52 रनों की तेज पारी खेली और उन्हें बेन डकेट ने 43 रनों के साथ अच्छा साथ दिया। भारत के गेंदबाज रनों को रोकने के लिए संघर्ष करते दिखे और अक्सर उनकी लाइन और लेंथ सही नहीं रही। लंच के बाद भारत ने वापसी की। प्रसिद्ध कृष्णा ने क्रॉउली को 64 रनों पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच करा दिया। इसके तुरंत बाद ओली पोप को मोहम्मद सिराज ने आउट कर दिया।

विराट कोहली-रोहित शर्मा और एमएस धोनी के साथ क्रिकेट खेलेंगे लियोनेल मेसी

एजेंसी नई दिल्ली

अर्जेंटीना के लीजेंड फुटबॉलर लियोनल मेसी अगर हाथ में बल्ला या गेंद पकड़े क्रिकेट खेलते हुए नजर आएं तो आपको कैसा लगेगा? अगर हम कहें कि यह सच होने वाला है फिर? जी हां, दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी को आप आने वाले कुछ समय में क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक, लियोनल मेसी दिसंबर में भारत का दौरा करने के लिए आएंगे। 13 से 15 दिसंबर के बीच मेसी मुंबई, कोलकाता और दिल्ली का दौरा करेंगे। टीओआई के मुताबिक, 14 दिसंबर को मेसी मुंबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम वानखेड़े में होंगे और सेवन अ साइड एक क्रिकेट मैच खेलेंगे। मेसी के साथ फील्ड पर दिग्गज क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मुंबई क्रिकेट ऐसोसिएशन ने इस बात की पुष्टि की है। एमसीए के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ' हां, मेसी 14 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम में एक इवेंट के लिए आने के लिए तैयार हैं। इवेंट के आयोजकों ने इवेंट के लिए इजाजत भी ली है। उनको परमिशन भी मिल गई है। कुछ सुपरस्टार क्रिकेटर भी इस इवेंट का हिस्सा होंगे।' 38 सा के लियोनल मेसी इससे पहले सिर्फ एक बार भारत आए हैं। वह 2011 में वेनेजुएला के खिलाफ फ्रेंडली मैच के खेलने के लिए भारत आए थे। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में वो मैच हुआ था। इसके अलावा मेसी के करियर की बात करें तो वह अब तक 8 बैलेन डी ओर जीत चुके हैं। वह 6 बार यूरोपियन गोल्डन शूज और 8 बार फीफा के बेस्ट प्लेयर रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 45 टीम ट्रॉफी जीती हैं। मेसी अब अगले साल फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी भाग ले सकते हैं।

व्यापार

अमेरिका की नाराजगी और दांव पर 590000 करोड़... अगर ट्रंप ने भारत को रूसी तेल से अलग किया तो पुतिन क्या करेंगे

एजेंसी नई दिल्ली

भारत और रूस के बीच गहरे संबंध हैं। दोनों देशों में व्यापारिक रिश्ते भी बेहद मजबूत हैं। लेकिन, अमेरिका के नए टैरिफ और प्रतिबंधों से इन रिश्तों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत को अपनी विदेश और आर्थिक नीति को लेकर मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। पूरे मामले के केंद्र में भारत का रूसी तेल आयात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल के आयात को रोकने का दबाव डाला है। इसके चलते रूस को होने वाले अरबों डॉलर के राजस्व पर खतरा मंडरा रहा है। व्लादिमीर पुतिन अमेरिका की अगुवाई वाली एक प्रमुख तेल पाइपलाइन को बंद करके जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे एक नया ग्लोबल सप्लाई संकट भी पैदा हो सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। 2022 से यह रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत रोजाना 20 लाख बैरल तक तेल खरीदता है। यह ग्लोबल सप्लाई का 2% है। चीन और तुर्की भी रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देश हैं। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों के अनुसार, भारत का रास्ता क्रेमलिन के लिए बहुत अहम है। अगर इसमें कोई बाधा आती है तो रूस कजाकिस्तान से सीपीसी पाइपलाइन को बंद करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस पाइपलाइन में अमेरिकी तेल कंपनियों शेवरॉन और एक्सॉन की बड़ी हिस्सेदारी है। यानी रूस के पास भी दबाव बनाने के तरीके हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर मॉस्को 7-9 अगस्त तक यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करता है तो वह रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक का टैरिफ लगा देंगे। भारत से अमेरिका में आने वाले सभी सामानों पर 25% का टैरिफ शुक्रवार से लागू है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने गुरुवार को बताया था कि ट्रंप की धमकी के बाद भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने इस सप्ताह रूसी तेल की खरीद रोक दी है। इसका मतलब साफ है। अगर भारत अमेरिकी दबाव के चलते रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो इसका असर सिर्फ रूस पर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता, ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी होगा। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर जा सकती हैं। भारत और रूस के बीच हमेशा से मजबूत रिश्ते रहे हैं। हाल के दिनों में व्यापार संबंध में जोरदार इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 68.7 अरब डॉलर (करीब 590000 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा महामारी से पहले के व्यापार का लगभग 5.8 गुना है। इस व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का है। रूस अब भारत की कुल तेल जरूरतों का 40% तक पूरा करता है। यह रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसमें रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं। भारत अपने सैन्य उपकरणों का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदता है। दोनों देशों के बीच परमाणु रिएक्टर बनाने के समझौते भी हैं। ट्रंप का दबाव इस मजबूत साझेदारी को कमजोर कर सकता है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा क्षमता दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यह भारत के लिए यह मुश्किल स्थिति है। उसे एक तरफ जहां रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना है। वहीं, दूसरी ओर अमेरिका के साथ अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक रिश्तों को भी सुरक्षित रखना है। यह पूरा मामला अब भारत की 68 अरब डॉलर की दुविधा पर आकर टिक गया है। ट्रंप की नीतियों से यह सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है।

अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर, भारत के बाहर जाने पर रोक, क्या बढ़ने वाली है मुसीबत

एजेंसी नई दिल्ली

अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के चेयरमैन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी किया है। इसका सीधा मतलब है कि उन पर देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। ईडी ने उन्हें 17,000 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। यह ऐक्शन मुंबई और अन्य शहरों में एडीएजी की कंपनियों से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी के बाद हुई है। ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुरू की गई है। जांच वित्तीय अनियमितताओं और लोन के गलत इस्तेमाल के एक जटिल नेटवर्क पर केंद्रित है। ईडी को शक है कि अनिल अंबानी ने लोन में गड़बड़ी की है। उन्होंने लोन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। जांच एजेंसी ने इस मामले में कई जगह छापेमारी की है। ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए भी बुलाया था। यह मामला 17,000 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड से जुड़ा है। 17,000 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी करना और यात्रा प्रतिबंध लगाना, यह दर्शाता है कि जांच एजेंसी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। अनिल अंबानी के खिलाफ एलओसी जारी करना सामान्य कदम नहीं है। यह तब किया जाता है जब जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इस कदम से सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अलर्ट जारी हो गया है। इससे अनिल अंबानी की विदेश यात्राओं पर रोक लग गई है। यह एक साफ संकेत है कि ईडी इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वह अनलि अंबानी की उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहती है। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर और सेबी जैसे अन्य नियामक निकायों की रिपोर्ट पर आधारित है। ईडी की जांच में लोन के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से, 2017 और 2019 के बीच यस बैंक की ओर से अंबानी की ग्रुप कंपनियों को दिए गए 3,000 करोड़ रुपये के लोन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जांचकर्ताओं ने कई अनियमितताओं की बात कही है। इसमें बैकडेटेड क्रेडिट अप्रूवल, उचित जांच की कमी और विभिन्न ग्रुपों और शेल कंपनियों को फंड का गलत इस्तेमाल शामिल है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ईडी एक फर्जी बैंक गारंटी रैकेट की भी जांच कर रहा है। इस जांच में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) को अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी की ओर से जमा की गई 68.2 करोड़ रुपये की एक फर्जी बैंक गारंटी का पता चला है। आरोप है कि यह फर्जी गारंटी एसबीआई की नकली ईमेल आईडी से भेजे गए जाली संचार के जरिए दी गई थी।

भारत को 'डेड इकॉनमी' बताने वाले ट्रंप के मुंह पर तमाचा, एक दिन बाद ही आए ऐसे आंकड़े कि पीट लेंगे माथा

एजेंसी नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा जड़ने वाले आंकड़े आ गए हैं। ट्रंप ने भले ही भारत की अर्थव्यवस्था को 'डेड इकॉनमी' कहकर मजाक उड़ाया है। लेकिन, जुलाई के जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) कलेक्शन के आंकड़े उनके दावे को पूरी तरह से खारिज करते हैं। जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है। अलबत्ता, यह भारत की आर्थिक मजबूती और तेज ग्रोथ का साफ प्रमाण भी है। बीते रोज केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी लोकसभा में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कुछ ही वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सरकार की बात का समर्थन करते हैं। जुलाई में सकल जीएसटी संग्रह में 7.5 फीसदी का मजबूत इजाफा हुआ है। यह बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन का यह आंकड़ा पिछले साल जुलाई के 1.82 लाख करोड़ रुपये और जून के 1.84 लाख करोड़ रुपये के संग्रह से काफी ज्यादा है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से घरेलू राजस्व में 6.7 फीसदी की बढ़ोतरी के कारण हुई है, जो देश के भीतर कंजम्पशन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं, बल्कि मजबूत रफ्तार है। यह ट्रंप के 'डेड इकॉनमी' के दावे को सीधे तौर पर चुनौती देती है। ईवाई इंडिया में टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने भी इन आंकड़ों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कुछ वैश्विक दबावों के बावजूद समग्र रुझान स्थिर उपभोग पैटर्न और अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास को बताता है। इसके अलावा, जीएसटी रिफंड में 66.8% की महत्वपूर्ण ग्रोथ यह दर्शाती है कि सरकार की नीतियां कंपनियों के लिए सहायक वातावरण बना रही हैं। जीएसटी रिफंड सालाना आधार पर बढ़कर 27,147 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। समय पर रिफंड मिलने से कंपनियों के पास जरूरी कार्यशील पूंजी बनी रहती है। इससे व्यापार की रफ्तार बनी रहती है। ये सभी फैक्टर मिलकर भारत की एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं ।

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक दयाराम दिव्य द्वारा मुद्रक वेदांत प्रभाकर, मेधा कम्प्यूटर्स एंड ऑफसेट प्रिंटर्स, ऑफिस नं. 128, वार्ड नं. 25, नंदभवन कांवाखेड़ा पार्क के पास, भीलवाड़ा 311001 (राज.) से मुद्रित एवं एस-20, प्रतापनगर, भीलवाड़ा (राज.) से प्रकाशित। संपादक दयाराम दिव्य 96949 57624, 87695 58132 * PRB एक्ट के तहत ख़बरों के चयन के लिए उत्तरदायी। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भीलवाड़ा होगा